Gyan Manthan
Journal homepage: www.gyanmanthan.org ISSN: **3108-3455**

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिलें के ग्राम पंचायतों का विकास

डॉ. अंजना ठाकुर
प्राचार्य
नवीन शासकीय महाविद्यालय, अर्जुनी विकासखण्ड–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
रामलाल पटेल
राजनीति विज्ञान, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय , जिला–दुर्ग (छ.ग.)

1.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर जिला भारत के उत्तर–पूर्व में स्थित है जों पंचायती राज प्रक्रिया और व्यवस्था की दृष्टि से संपन्न जिला है। यहां की ग्रामीण विकास की प्रक्रिया काफी व्यवस्थित और प्रगतिशील रही है। बिलासपुर जिला अपने आप में बहुत ही समृद्ध है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की न्यायधानी होने के कारण यहां के पंचायतों में हमें प्रशासनिक सक्रियता और नवाचार का बहुत ही अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। बिलासपुर जिलें की अधिक्तर जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में निवास करती है और अपने जीवकोपार्जन के साधन की उपलब्धता के लिए कृषि कार्यो पर निर्भर रहती है। बिलासपुर जिला मध्य भारत के प्रमुख केन्द्रों में से एक होने के कारण इसका गठन और विकास बहुत से प्रशासनिक चरणों से होकर गुजरा हुआ है। बिलासपुर जिलें के ग्राम पंचायतों के विकास में बहुत सी चीजे सहायक है जो एक परम्परागत ग्राम पंचायत को आधुनिक ग्राम पंचायत के रूप में विकसीत करती है, और उसे डिजिटलीकरण से जोड़कर सरकार की योजनाओं को दुरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक पहुचाने का कार्य कर रही है।

GYAN MANTHAN A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

1.2 बिलासपुर जिलें की संपुर्ण जानकारी

बिलासपुर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो हमें यह जानकारी मिलती है कि बिलासपुर का निर्माण लगभग 400 वर्ष पूर्व बिलासा बाई केवटिन के नाम से हुआ था। बिलासा बाई एक मछवारन, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय एकता का प्रतिक थी। बिलासपुर जिले का रतनपुर क्षेत्र कल्चुरी राजाओं के शासन काल के समय राज्य की राजधानी रही है तथा इस क्षेत्र में 1741 से मराठा शासकों ने भी शासन किया था। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात राज्य में कुल पांच संभाग है, जिसमें से एक संभाग बिलाासपुर भी है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आठ जिलें आते है जिसमें से एक जिला बिलासपुर है। बिलासपुर जिले का निर्माण 1861 में अंग्रेजों को शासन काल के दौरान से ही हो गया था। अंग्रेजों ने बिलासपुर क्षेत्र को अपने व्यापारिक लेन–देन का केन्द्र बनाया हुआ था। देश की आजादी के बाद बिलासपुर जिले ने अपने विकास की ओर कदम रखा और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक तीनों ही दृष्टि से विकास की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया था। बिलासपुर जिले की वास्तविक पहचान छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद सामने आयी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दुसरे सबसे बड़े शहर के रूप में विख्यात है। यह शहर अरपा नदी के किनारे स्थित है। यहां शहरी के साथ ही साथ ग्रामीण जनसंख्या भी बहुतायत रूप में उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बिलासपुर ''**दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे**'' का मुख्यालय होने के कारण भी प्रसिद्ध है। जिले के निर्माण के साथ ही यहां कई औद्योगिक क्षेत्रों जैसे कि सिरगिट्टी, तिफरा और सिलपहरी का भी निर्माण हुआ है।

तालिका क्र. 1

बिलासपुर जिलें में ग्राम और ग्राम पंचायतों की संख्या

क्र.	लोकल बॉडी का नाम (ब्लाक)	संमलित पंचायत	संमलित ग्राम
1.	बिल्हा	139	174
2.	कोटा	101	162

3.	मस्तुरी	126	173
4.	तखतपुर	117	178

- **राजनीतिक महत्व** – बिलासपुर जिला राज्य की सत्ता और सियासत में अपना एक राजनीतिक महत्व रखता है। इसे सत्ता और सियासत की दृष्टि से एक बड़े केन्द्र के रूप में माना जाता है। बिलासपुर जिला राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जादा संवेदनशील और जागरूक माना जाता है। यहां का विधानसभा क्षेत्र **बिलासपुर, बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मस्तुरी और बेलतरा** ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार का क्षेत्र राज्य की सत्ता की चाबी मानी जाती है। इस क्षेत्र से अनेको दिग्गज नेता उभर कर सामने आए हुए है जिन्होंने राज्य की राजनीति को विकास की गति की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। वर्तमान में भी राज्य की राजनीति में इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता शासन के उच्च पदों से जुडकर क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे है।
- **प्रशासनिक महत्व** – बिलासपुर जिला राज्य के प्रशासनिक केन्द्रों में अपना अलग ही महत्व रखता है राज्य की राजधानी के प्रशाासनिक महत्व के बाद बिलासपुर जिला दुसरे स्तर पर है। बिलासपुर को राज्य की न्यायधानी कहा जाता है, क्योकि यहां राज्य का ''**उच्च न्यायालय**'' स्थित है। इसी के कारण राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिक्षक आदि विभागों का सीधा समन्वय बिलासपुर जिले से रहता है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पांच संभागों में से एक है। इस संभाग में वर्तमान में 8 जिले आते है जिनका प्रशासन बिलासपुर जिले से ही होता है, जिस कारण से प्रशासनिक दृष्टि से बिलासपुर जिले का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
- **आर्थिक महत्व** – बिलासपुर जिला **उर्जा, कोयला, रेलवे और कृषि** पर आधारित उद्योगों का बहुत बड़ा केन्द्र है। बिलासपुर जिले का राज्य के औद्योगिक विकास और वित्तीय स्थिरता में अतुलनीय योगदान रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी कंपनी ''**साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**'' **(SECL)** का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है, जो अधिक मुनाफा कमाने वाली कंपनीयों में से एक है।

GYAN MANTHAN
A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

बिलासपुर मे ''**दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे**'' **(SECR)** का मुख्यालय स्थित है। यहां से अधिक्तर माल जैसे – **कोयला, सीमेंट, लोहा, अनाज** आदि का अलग अलग राज्यों में निर्यात किया जाता है। ''**एनटीपीसी सीपत**'' राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम भी बिलासपुर जिले में स्थित है, जहां से अलग–अलग राज्यों को बिजली का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा जिलें का **कोसा सिल्क, राइस मिल्स उद्योग, धान की पैदावार** आदि के लिए भी महत्व है।

- **शैक्षणिक महत्व –** बिलासपुर जिलें में राज्य का एक मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय ''**गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छ.ग.**''स्थित है। जिसमे राज्य के विद्यार्थीयों के अलावा देशभर के अलग अलग राज्यों से भी छात्र–छात्राएं पढ़ने आते है। इसके साथ ही साथ अंग्रेजी शासनकाल में निर्मित ''**आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान**'' **(ITI)** भी स्थित है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा आईटीआई माना जाता है। इसके अलावा यहां ''**अटल बिहारी वाजपायी विश्वविद्यालय**'' स्थित है जो राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है। इसके सम्बद्ध बहुत से कॉलेज जुड़े हुए है। अनेको कोचिंग संस्थान, बड़े–बड़े कॉलेज, स्कुल स्थित है, जिस कारण से बिलासपुर जिलें का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।

GYAN MANTHAN
A MULITIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

1.3 बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायतों का विकास

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का विकास राज्य के निर्माण के पश्चात तीव्र गति से प्रारम्भ हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत इस क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागु किया गया है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत तीन भागों में स्थानीय शासन की ईकाईयों को विभक्त किया गया है, जिससे जिलें के प्रत्येक ग्राम पंचायतों को शासन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़कर शासन में सहभागी बनाया जा सके। पंचायतों को शक्ति देकर सरकार जमीनी स्तर के लोगों की शासन में शामिल कर रही है और विकास की गति को तीव्र कर रही है। शासन के द्वारा ग्राम पंचायतों का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढ़ांचे को अधिक प्रगतिशील बनाने तथा उसे मजबुती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। बिलासपुर राज्य की न्यायधानी होने के कारण हमें यहां की पंयायतों में प्रशासनिक सक्रियता और

नवाचार का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। जिलें में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभुत सुविधाओं तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से लगातार पंचायतों का विकास किया जा रहा है।

1.4 पंचायतों का विकास

- **डिजिटल और ई–गवर्नेस का विस्तार –** जिले के पंचायतों को डिजिटल बनाने और उसे डिजिटलीकरण से जोड़ने के लिए अधिकांश पंचायतों को ''**ई–पंचायत**'' मिशन के तहत जोड़ा गया है। इससे आनलाईन भुगतान की सुविधा, आनलाईन जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र, आय–व्यय का ब्यौरा, सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण, आनलाईन आवेदन की सुविधा आदि की व्यवस्था की गयी है, जिससे पंचायतों के कार्यो में पारदर्शिता बढ़ी है और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पष्टता बढ़ी है। ''**भारत नेट योजना**'' के तहत सरकार ''**डिजिटल विलेज योजना**'' की अवधारणा को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन सेवा पहुंचाने और पंचायतों को ऑप्टीकल फाईबर केबल के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ''**हमर छत्तीसगढ़ योजना**'' के तहत कई पंचायतों में मॉडल सचिवालय को भी विकसीत किया गया है।
- **पंचायतों के बुनियादी ढ़ांचे को निर्माण–** सरकार जिले में पंचायती कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नये–नये पंचायत भवनों का निर्माण कर उसके मुलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करायी है। इन पंचायतों के माध्यम से पुराने स्कूलों का जीर्णोद्धार और नये–नयें आंगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण पर भी अपना ध्यान केन्द्रीत किया है। पंचायतों को शहरों के मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना के माध्यम से सड़क बनाकर आवागमन को आसान बनाया है। मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना के द्वारा दूरस्थ गांवों के प्रत्येक छोर तक कनेक्टीविटी को बढ़ाया गया है। पंचायतों को मजबुत बनाने के लिए सड़कों के साथ ही साथ नाली, पुलिया तथा सामुदायिक भवनों आदि का भी निर्माण कार्य किया गया है।

GYAN MANTHAN A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

- **स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार–** जिले के दुरस्थ वनांचल क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों में रहने वाले जारूरतमंद लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं को पहूंचाने के लिए सरकार ने ''**मुख्यमंत्री मोबाईल चिकित्सालय योजना**'' का संचालन कर रही है। इसके तहत दुरस्थ ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त इलाज, दवाईयां और स्वास्थ्य जांच की सुविधा उनके निवास स्थान तक मुहैया करायी जा रही है। इसके साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप–स्वास्थ्य केन्द्र और आरोग्य मंदिर को स्थापित किया गया है, जिससे गांव गांव तक स्वास्थ्य सुविधा को पहुचाया जा सके।
- **ग्राम में स्वच्छता को बढ़ावा तथा पेयजल की व्यवस्था–** स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायतों ने स्वच्छता अभियान में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया है। अपने ग्राम को स्वच्छ और साफ रखने के लिए पंचायतों ने ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट दोनों प्रकार के कचरे के प्रबंधन और व्यवस्थित निष्पादन पर बल दिया है। पंचायतों ने अनेक प्रकार के सफाई अभियान भी चलाए है जिसके चलते ग्राम के आस–पास गंदगी फैलाने वाले कचरे का व्यवस्थीत रूप से निष्पादन करने में सफल हुए है। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का भी कार्य किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों के प्रत्येक घरों में शौचालय का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए ''**हर घर नल योजना**'' का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके तहत गांव के प्रत्येक घरों में सरकार के द्वारा टेपनल की व्यवस्था की गयी है, जिसके माध्यम से दुरस्थ्य क्षेत्रों के गांव के घरों में पेयजल को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है।
- **शिक्षा का विकास–** बिलासपुर जिले में स्कुली शिक्षा के विस्तार के तहत ''**स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय**'' और ''**स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय**'' एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है। यह स्कुली शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में हमे बहुत जादा विकास विकास देखने को मिलता है। इस योजना के

तहत शहरी एवं ग्रामीण इलाको के बहुत से स्कुलों को अत्यधिक आधुनिक रूप में परिवर्तित किया गया है। इसमें निजी स्कुलों के जैसी ही आधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स के साधनो की व्यवस्था की गयी है। यहां पठन–पाठन की सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध करायी जाती है। पढ़ाने के लिए स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। इसे देखते हुए हम कह सकते है कि सरकार की इस पहल से अब गांव के बच्चे भी सरकारी स्कुल में निजी स्कुलों की भांति अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर सकते है और अपने व्यक्तित्व और भविष्य को एक नई दिशा की ओर मोड़ सकते है। इसके अलावा क्षेत्र में **पीएमश्री स्कूल, आदिम जाति कल्याण स्कुल** आदि की भी व्यवस्था है जों बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायतों के विकास की दिशा को नया रूप प्रदान करते है।

- **आर्थिक विकास–** पिछले कुछ वर्षो बिलासपुर जिलें के ग्राम पंचायतों के आर्थिक विकास में तेजी से वृद्धि हुई है। पूर्व की भांति पंचायतें केवल सरकारी अनुदान पर निर्भर न रहने के बजाए आत्मनिर्भता की ओर बढ़ रही है, जिसके चलते पंचायतें स्थानीय संसाधन, कृषि संसाधनों और महिला स्वयं सहायता समुहों को बढ़ावा दे रही है। वर्तमान डिजिटलीकरण के समय में पंचायतों में अब बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ कर दिया गया है जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाएं बैंक सखी के रूप में कार्य कर पैसे निकालने व जमा करने का कार्य कर रही है। ग्रामिण लोग आनलाईन पोर्टल के माध्यम से सरकार से वित्तीय सहायता संबंधित जानकारी प्राप्त कर स्वयं का लघु उद्योग प्रारंभ कर रहे है।
- **कृषि एवं सिंचाई का विकास –** छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसमें बिलासपुर जिला अपनी अग्रणी भूमिका निभाता है। वर्तमान में जिलें के ग्राम पंचायतों ने पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए, आधुनिक खेती, जैविक खेती और फसल विविधिकरण को अपनाते हुए कृषि क्षेत्र में विकास की क्रांति को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिले के ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण के लिए तालाब खुदाई कर मतस्य पालन और जल को संरक्षित रखकर सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। किसानों की

फसलों के जलापूर्ति के लिए तालाबों नहरों और कुंए का निर्माण और मरम्मद किया गया है, साथ ही साथ फसलों की पैदावार बढ़ानें के लिए किसानों को उन्नत बीज, खाद एवं कृषि उपकरण मुहैया कराया जा रहा है। छोट–छोटे कृषि उपकरणों के लिए सरकार के द्वारा कृषि ऋण भी प्रदान भी किया जा रहा है, जिसकी मदद से ग्रामीणों को कृषि कार्यो को करने में सहायता मिल रही है।

1.5 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के पंचायतों के विकास का सफर यह स्पष्ट करता है कि अब पंचायत अपने पारंपरिक विकास के कार्यों तक ही सीमित नही रहा है, यह पंचायतों के आर्थिक स्वावलम्बन, पंचायतो में पारदर्शिता, आनलाईन डिजिटलीकरण, डिजिटल गवर्नेंस जैसे अनेक लक्ष्यों के साथ लेकर चल रहा है। पंचायतो में अब डिजिटल कनेक्टीविटी, शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पंचायत अब सस्टनेबल डेवेलपमेंट मॉडल की ओर बढ़ रहा है। सरकार के द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत और उसमें रह रहे इस क्षेत्र के लोगों के स्तर का विकास देखने को मिलता है। ग्रामीण इलाकों के लोगों की आजीविका में हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। पंचायतों के विकास से खुलेपन को बढ़ावा मिला है जिससे अब पंचायतों की कार्यप्रणाली में स्थानीय महिलाएं, युवा, नौजवान सभी बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते है और अपने विचारो के पंचायत के समक्ष रख कर स्थानीय समस्यों का समाधान करने में अपनी भुमिका अदा करते है। किन्तु अनेक दुरस्थ ग्रामीण वन क्षेत्रों के पंचायतों में हमें अभी भी पिछड़ापन देखने को मिल ही जाता है।

1.6 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. वर्मा, आर. के. (2021). बिलासपुर का प्रशासनिक एवं सामाजिक इतिहास. रायपुरः वैभव प्रकाशन।
2. शर्मा, डॉ. रामकुमार (2015). छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था एवं कृषि विकास. बिलासपुरः अरपा प्रकाशन।

GYAN MANTHAN
A MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL

3. तिवारी, अंजली (2022). छत्तीसगढ़ में महिला सरपंचो की भूमिका एवं लैंगिक सशक्तिकरणः बिलासपुर जिले के विशेष संदर्भ में. बिलासपुरः गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन. रायपुरः विकास आयुक्त कार्यालय।
5. ई–ग्राम स्वराज एवं डिजिटल पंचायत पहलः बिलासपुर जिला रिपोर्ट।
6. https://bilaspur.gov.in
7. Bilaspur district के विकास खंड एवं पंचायत आंकड़े। https://villageinfo.in

GYAN MANTHAN
A MULITIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL